उत्तर प्रदेश ने WEF 2025 में कृषि, आपदा प्रबंधन और जनसुनवाई-समाधान में डिजिटल परिवर्तन के लिए एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ साझेदारी की

लखनऊ, 22 जनवरी, 2025:

दावोस में विश्व आर्थिक मंच (WEF) 2025 सम्मेलन के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि, आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए एचसीएल सॉफ्टवेयर के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी का उद्देश्य उन्नत एआई और डेटा-संचालित समाधानों का उपयोग करके नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और आपदा प्रबंधन की क्षमताओं को मजबूत करना है।

एचसीएल सॉफ्टवेयर राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि नवाचार के लिए एआई-संचालित प्लेटफॉर्म लागू करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को अत्याधुनिक डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाना, उनकी उत्पादकता को बढ़ावा देना और जलवायु चुनौतियों के प्रति उनकी लचीलापन क्षमता को मजबूत करना है। इस साझेदारी के तहत, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और अवधारणा के प्रमाण (Proof of Concept) पहले से ही चल रहे हैं, और व्यापक कार्यान्वयन की योजना बनाई जा रही है।

इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसुनवाई-समाधान शिकायत निवारण प्रणाली को एआई-आधारित स्वचालन से आधुनिक बनाने की भी घोषणा की। इस अपग्रेड से शिकायतों के निपटान, रूटिंग और विश्लेषण को सुव्यवस्थित किया जाएगा, जिससे सरकार और नागरिकों के बीच जुड़ाव और उत्तरदायित्व में महत्वपूर्ण सुधार होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री अमित सिंह ने कहा, "एचसीएल सॉफ्टवेयर की एआई क्षमताओं को जनसुनवाई-समाधान प्रणाली में एकीकृत करके, हम एक अगली पीढ़ी का शिकायत निवारण मंच स्थापित कर रहे हैं, जो यूपी में लाखों लोगों को प्रभावित करेगा और समाधान की गति को तेज करेगा।"

एचसीएल सॉफ्टवेयर के मुख्य राजस्व अधिकारी श्री राजीव शेष ने कहा, "यह साझेदारी डिजिटल शासन और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। एचसीएल सॉफ्टवेयर के एआई के साथ यूपी सरकार की नागरिकों की जरूरतों की गहरी समझ को मिलाकर, हम स्मार्ट शासन के लिए एक खाका तैयार कर रहे हैं, जो लाखों लोगों को लाभ पहुंचाएगा।"

इस साझेदारी का एक प्रमुख पहलू नोएडा में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) की स्थापना है, जिसकी घोषणा डब्ल्यूईएफ कार्यक्रम के दौरान की गई। यह सेंटर कृषि, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए एआई-संचालित समाधानों का नेतृत्व करेगा और सरकारी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह केंद्र राज्य के विकास को गति देने और मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा।

विश्व आर्थिक मंच 2025 में शुरू की गई यह साझेदारी, उत्तर प्रदेश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सतत विकास और बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है।